नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स

एनआईयू की स्टडी रिपोर्ट देखेने के लिए यहां क्लिक करें

अनुसंधान, प्रशिक्षण और शहरी विकास और प्रबंधन में सूचना के प्रचार हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एक प्रमुख संस्थान है । समिति पंजीकरण अधिनियम के तहत इसका गठन एक स्वायत्त निकाय के रुप में 1976 में हुआ था, संस्थान को शहरी मामले और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों, शहरी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण तथा शहरी मामलों से संबंधित अन्य एजेंसियों का सहायोग और सुविधाएं प्राप्त हैं । संस्थान की नीतियां और निर्देश, शासी परिषद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, भारत सरकार के तीन सदस्य उनकी पदेन क्षमता सहित, 12 अन्य सदस्य और निदेशक जो संस्थान के मुख्य कार्यकारी है, और सदस्य सचिव शामिल हैं ।

संस्थान का मुख्य कार्य, सुशिक्षित, अनुभवी, शहरी आयोजकों की बहुअनुशासनिक टीम, भूगोलज्ञ सांख्यिकीविद, समाज शास्त्रियों और प्रबंधन विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा । आधुनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर और आधुनिक सॉफ्टवेयर पैकेज से सुसज्जित विशेषज्ञ स्टॉफ संस्थान के अनुसंधान कार्य, प्रशिक्षण, प्रकाशन और अन्य क्रियाकलापों में आवश्यक सेवाओं में सहयोग प्रदान करता है ।

शहरी नीति के निर्माण में सहयोग

- संस्थान में, शहरी शासन में मुद्दों को उठाने के लिए कार्यबद्ध कार्य किया गया है जिससे 74वें संविधान संशोधन एक्ट, 1992 की ड्राफ्टिंग में सहायता मिली ।
- संस्थान द्वारा किए गए व्यापक कार्य से राष्ट्रीय आयोग को शहरीकरण पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में सहायता मिली ।
- जब से 75वें प्लान के तहत यूबीएसपी कार्यक्रम शुरु किया गया है तब से संस्थान में, भागीदारी प्रशिक्षण और शहरी बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान का कार्य जारी हे जिससे शहरी गरीबी उपशमन के लिए सामुदायिक प्रक्रिया निर्माण सहायोग प्राप्त हुआ है ।
- संस्थान में राष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित की गई है जिसमें नगरीय वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न मामलों पर राज्य वित्त आयोग को तकनीकी सहायता प्रदान की गई ।
- इन्डो-यूएसएड सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यशालाएं, सेमिनार तथा अनुसंधान, वित्तीय संस्थान सुधार और विस्तार(एफआईआरई-डी) कार्यक्रम, जो संस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं , में राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष प्रभार्य शहरी अवस्थापना हेतु पूर्ण लागत वसूली की संकल्पना के बारे में जानकारी दी जाती हे और शहर शासन और क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि के लिए प्रेरित किया जाता है ।

अनुसंधान के जरुरी क्षेत्र

- शहरीकरण और शहरी नीति
- शहरी आयोजना और विकास
- शहरी अवस्थापना और सेवाएं
- शहरी गरीबी
- शहरी पर्यावरण
- शहरी परिवहन

- शहरी आवास
- नगर वित्तपोषण
- शहरी अनौपचारिक क्षेत्र

प्रकाशन एवं प्रलेखन

संस्थान अपने प्रकाशन एवं प्रलेखन सेवाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्र पर अपने अनुसंधान आउटपुट एवं अन्य संबंधित सूचना का प्रचार एवं आदान प्रदान करती है । संस्था के अनुसंधान सभी संबद्ध से अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला एवं वर्किंग पेपर के माध्यम से बहुत कम लागत पर उपलब्ध है ।

जर्नल एवं अन्य पिरियाडिकल्स

- इस क्षेत्र में मुख्य अर्द्ध वार्षिक जर्नल, शहरी भारत, भारत के शहरी क्षेत्र के अनुसंधान एवं अध्ययन में इच्छुक निर्णय निर्माताओं एवं पेशेवरों तथा अनुसंधानों से योगदान प्रकाशित करती है ।
- शहरी समस्याओं एवं संबंधित मुद्दों पर समाचारपत्रों का तैयार संकलन 'शहरी समाचार' अनुसंधानों, नीति निर्माताओं एवं प्रशासकों हेतु संदर्भ अच्छा स्रोत है ।
- 80 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित लेखों की अद्धवार्षिक ग्रंथसूची 'अर्बन फाइल' शहरी क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए व्यापक महत्व का है ।

अनुसंधान अध्ययन श्रृंखला/कार्य संबंधी कागजात

संस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन इस प्रकार हैः-

- भारत में शहरी अवस्थापना को वित्तपोषण
- मैसूर का आंतरिक शहरी पर्यावरण और शहरी नवीकरण ।
- भारत में शहरी सेवाओं के निजीकरण का क्षेत्र और कार्य ।
- ओक्टरोएः नगर वित्तपोषण और परिवहन क्षमता ।
- भारत के शहरी क्षेत्र की रुपरेखा ।
- शहरी सेवाओं की कीमत और लागत वसूलीः चार भारतीय शहरों की एक केस स्टडी ।

300 शहरों/कस्बों में जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति पर एनआईयूए स्टडी रिपोर्ट

1. जलापूर्ति और जल किराया 1999
2. वेस्ट वाटर प्रबंधन और कम लागत सफाई व्यवस्था 1999
3. ठोस कचरा प्रबंधन 1999
4. शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति(भाग 1, भाग 2,भाग 3, भाग 4)

वेबसाईट देखें ।

http://www.niua.org